

सम्पादकीय



अभियंकित हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है,
सत्य प्रस्तुत करना हमारा कर्त्तव्य

भारत को नुकसान जवाबदेही भाजपा की ही होगी

देश के अंदर सियासी तू-तू-मैं में दीप रह गहल है, मार जिस अमेरिका के साथ भारत का निकट संबंध बनाना मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है, उसी पर अब इतना गंभीर इलाजम सत्ताधारी भाजपा ने लगा दिया है। भाजपा सत्ताधारी पार्टी है। उसे यह खाल अवश्य रखना चाहिए कि वह जो बोलती है, उससे भारत सरकार की राय से जोड़ कर देखा जाएगा। देश के अंदर सियासी चर्चा का स्थान इतना गिर चुका है कि अब कौन, क्या बोलता है, उस पर ज्यादा माथापच्ची करने के लिए महसूस नहीं होती है। लेकिन जो बातें और जीवन के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित कर सकती हैं, उस मामलों में अपेक्षा अवश्य रहती है कि सत्ताधारी दल के नेता जिम्मेदारी से बोलेंगे। वे खाल रखेंगे कि उनकी बातों का दूरगामी प्रभाव हो सकता है। इसीलिए भाजपा ने जिस तरह अब अमेरिका के विदेश मंत्रालय और डीप स्टेट पर निशाना साधा है, उससे व्यग्रता पैदा होती है।

पार्टी के मुताबिक अमेरिका विदेश मंत्रालय और डीप स्टेट के कुछ तत्व कुछ खोजी प्रत्येकों और विषय के नेता राहुल गांधी के साथ मिल कर भारत को अस्थिर करने में जुटा हुआ है। ताजा संदर्भ अडानी समूह के खिलाफ अमेरिका में दारत्रय मुदकों का, जिससे पार्टी ने प्रत्यक्षों के समूह आर्नांडेंड क्राइम एंड कारप्रॉप्रो ग्रोवर की ओर लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना और लोकसभा व सभी विधानसभाओं के कार्यकाल से जुड़े जल्दी बदलाव किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने इससे पहले सिंतंबर में पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट मंजूर कर ली थी, जिसकी सिफारिशों के आधार पर ये विधेयक तैयार किए गए हैं।

श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति ने बानी गई इसी तभी से इसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। विषय पूछ रहा है कि इसका क्रियान्वयन कैसे होगा? अगर 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ सभी राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव कराना हैं तो अगे वार साल में होने वाले विधानसभा चुनावों का क्या होगा? यह भी पूछा जा रहा है कि अगर लोकसभा और सभी विधानसभाओं का कार्यकाल तय कर दिया जाएगा तो बीच में सरकार ने बहुत गंवाया या सरकार गिरी तब क्या होगा? क्या वह राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा और अगले लोकसभा चुनाव के साथ ही वहं चुनाव होगा? वैसे इन सभी सवालों का जवाब सरकार की ओर से प्रत्यावर्ती विधेयक में मिल जाएगा। परंतु अगर राजनीतिक पूर्वाग्रह जोड़ दें तो इन सवालों के जवाब बहुत मुश्किल नहीं हैं। कुछ विधानसभाओं के कार्यकाल बड़ा कर और कुछ के कार्यकाल घटा कर सभी विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा के साथ कराए जा रही हैं। सरकार इस मामले में आम राय बनाने की ही होगी।



बंगलुरु के जगन्नाथ भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए

बीजेपी एमएलसी संदीप रवि.

वन नेशन, वन इलेक्शन से विकास की नई ऊंचाइयों को हासिल करेगा देश

एस. सुनील

सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि हमेशा चलने वाले चुनावों पर विराम लग जाएगा। सरकारों का आन विकास कार्यों की ओर होगा। आचार सहित की वज्र से विकास कार्य टप्प नहीं होगे। और सबसे ऊपर हर बार चुनाव में होने वाले वेहिसाव खर्चों पर लगाम लगेगी। चुनाव आयोग से लेकर राजनीतिक दलों का चुनावों पर वेहिसाव खर्च होता है। एक साथ चुनाव से इन खर्चों में कटौती होगी। सुरक्षा बलों को भी लगातार इस राज्य से उस राज्य तक यात्रा करनी पड़ती है। आम लोगों का आन भी चुनाव पर लगा रहता है। यह सब कुछ एक निर्णय से बदल जाएगा।

देश सचमुच बदल रहा है। न सिर्फ बदल रहा है, बल्कि शक्तिशाली हो रहा है। देश में अधिक और राजनीतिक स्थिरता आई है। अभी जिस समय देश संविधान अंगीकार करने के 75 साल पूरे होने का उत्सव मना रहा है, प्रधानमंत्री श्री नंदेंद्र मोदी की सरकार ने एक और ऐतिहासिक निर्णय किया है। केंद्रीय मर्मिंडल ने एक देश के, 'चुनाव' के लिए बनाए गए दो विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद में शक्तिशाली नेता जिम्मेदारी से बोलेंगे। वे खाल रखेंगे कि उनकी बातों का दूरगामी प्रभाव हो सकता है। इसीलिए भाजपा ने जिस तरह अब अमेरिका के विदेश मंत्रालय और डीप स्टेट पर निशाना साधा है, उससे व्यग्रता पैदा होती है।

पार्टी के मुताबिक अमेरिका विदेश मंत्रालय और डीप स्टेट के कुछ तत्व कुछ खोजी प्रत्येकों और विषय के नेता राहुल महसूस नहीं होती है। ताजा संदर्भ अडानी समूह के खिलाफ अमेरिका में दारत्रय मुदकों का, जिससे पार्टी ने प्रत्यक्षों के समूह आर्नांडेंड क्राइम एंड कारप्रॉप्रो ग्रोवर की ओर लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना और लोकसभा व सभी विधानसभाओं के कार्यकाल से जुड़े जल्दी बदलाव किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने इससे पहले सिंतंबर में पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट मंजूर कर ली थी, जिसकी सिफारिशों के आधार पर ये विधेयक तैयार किए गए हैं।

श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति ने बानी गई इसी तभी से इसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। विषय पूछ रहा है कि इसका क्रियान्वयन कैसे होगा? अगर 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ सभी राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव कराना हैं तो अगे वार साल में होने वाले विधानसभा चुनावों का क्या होगा? यह भी पूछा जा रहा है कि अगर लोकसभा और सभी विधानसभाओं का कार्यकाल तय कर दिया जाएगा तो बीच में सरकार ने बहुत गंवाया या सरकार गिरी तब क्या होगा? क्या वह राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा और अगले लोकसभा चुनाव के साथ ही वहं चुनाव होगा? वैसे इन सभी सवालों का जवाब सरकार की ओर से प्रत्यावर्ती विधेयक में मिल जाएगा। परंतु अगर राजनीतिक पूर्वाग्रह जोड़ दें तो इन सवालों के जवाब बहुत मुश्किल नहीं हैं। कुछ विधानसभाओं के कार्यकाल बड़ा कर और कुछ के कार्यकाल घटा कर सभी विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा के साथ कराए जा रही हैं।



का प्रयास कर रही है। इसलिए संविधान संशोधन के विधेयक पेश करने के बाद उसे संयुक्त संसदीय समिति वाली जेपीसी को भेजा जा सकता है, जहाँ सभी पार्टियों के सांसद इस पर विचार करेंगे। यह समिति सभी संघीय पक्षों से सलाह मर्शिवरा करेगी और आम लोगों की राय भी लेगी। उसके बाद समिति बना कर इसे पास कराया जाएगा। वैसे सरकार जब चाहती तब इसे पास करा सकती थी व्यक्तियों ये साधारण संघीय हैं, जिनके लिए संसद में साधारण बहुमत की जरूरत है और राज्यों की विधानसभा चुनाव जैसा क्षमता वाला विधेयक होना चाहिए।

जिस समय श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी तभी से इसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। विषय पूछ रहा है कि इसका क्रियान्वयन कैसे होगा? अगर 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ सभी राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव कराना हैं तो अगे वार साल में होने वाले विधानसभा चुनावों का क्या होगा? यह भी पूछा जा रहा है कि अगर लोकसभा और सभी विधानसभाओं का कार्यकाल तय कर दिया जाएगा तो बीच में सरकार ने बहुत गंवाया या सरकार गिरी तब क्या होगा? क्या वह राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा और अगले लोकसभा चुनाव के साथ ही वहं चुनाव होगा? वैसे इन सभी सवालों का जवाब सरकार की ओर से ऐसे तरह दिए जा रहे हैं, जिनसे खुद ही विषयक पार्टियों के बोलाएंगे। कांग्रेस और डीप विधायिकी पार्टियों लोकसभा चुनाव को प्रतिवाद कर रही हैं। विषय की ओर से बोलाएंगे। विधायिकी पार्टियों के बोलाएंगे। लोकसभा चुनाव को बहुत मुश्किल नहीं है।

क्या देश के पहले दिन से इस प्रस्ताव का विरोध किया जा रहा है?

विषय का क्रियान्वयन कैसे होगा? विषय को सरकार के हर प्रस्ताव और हर अच्छी पहल का विरोध करना है इतनालिए वह विरोध कर रही है। विरोध में विषय की ओर से ऐसे तरह दिए जा रहे हैं, जिनसे खुद ही विषयक पार्टियों के बोलाएंगे। लोकसभा चुनाव को विरोधी बोल जाएंगे। विषय की ओर से ऐसे तरह दिए जाएंगे, जिनके लिए संसद में साधारण बहुमत की जरूरत है और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव को लोकसभा के बोलाएंगे।

क्या देश के पहले दिन से इस प्रस्ताव का विरोध किया जा रहा है?

विषय की ओर से ऐसे तरह दिए जाएंगे, जिनसे खुद ही विषयक पार्टियों के बोलाएंगे। विषय की ओर से ऐसे तरह दिए जाएंगे, जिनके लिए संसद में साधारण बहुमत की जरूरत है और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव को लोकसभा के बोलाएंगे।

क्या देश के पहले दिन से इस प्रस्ताव का विरोध किया जा रहा है?

विषय की ओर से ऐसे तरह दिए जाएंगे, जिनके लिए संसद में साधारण बहुमत की जरूरत है और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव को लोकसभा के बोलाएंगे।

क्या देश के पहले दिन से इस प्रस्ताव का विरोध किया जा रहा है?

विषय की ओर से ऐसे तरह दिए जाएंगे, जिनके लिए संसद में साधारण बहुमत की जरूरत है और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव को लोकसभा के बोलाएंगे।

क्या देश के पहले द

